



मोपाल, सोमवार

13

जुलाई 2026

Email.kalpriyanews72@gmail.com

आषाढ़ कृष्ण पक्ष-14, विक्रम संवत् 2083

पेज-6

केजरीवाल बोले- राममंदिर के चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी

महंत कमलनयन ने कहा- चंपत राय चोर नहीं

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि चंदा चोरों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। भाजपा ने भगवान राम के नाम पर चोट मांगकर केंद्र और 21 राज्यों में सरकार बनाई। बदले में प्रभु श्रीराम के साथ विश्वासघात किया। इधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण में चंपत राय का बड़ा योगदान रहा है। लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की।



राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की टीम 22 जुलाई के बाद कमान संभाल सकती है। इस पर मंथन चल रहा है। पुलिस आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नु और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर ले सकती है। दोनों को सोमवार को फैजाबाद कोर्ट में पेश करेगी और 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। गोरखपुर में चढ़ावा चोरी को लेकर पोस्टर लगवाने वाले सपा नेता अरविंद शुक्ला समेत 3 लोगों को पुलिस ने शनिवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने शुक्रवार रात पोस्टर लगाए थे। जिस पर लिखा था- ‘राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया दान अपना।

फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर

नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला

मुंबई (एजेंसी)

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी फॉर्च्यून इंडिया की सबसे पावरफुल टॉप-100 महिलाओं की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया हैं। यह सम्मान उन्हें लीडरशिप और समाज सेवा के लिए मिला है। उनकी लीडरशिप में फाउंडेशन ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए 2.9 करोड़ बच्चों समेत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों



की जिंदगी बदली है। इवेंट में नीता अंबानी ने कहा, लीडरशिप को करुणा, समावेश और सशक्तिकरण से परिभाषित किया जाना चाहिए। मेरे लिए सच्ची पावर दूसरों को सशक्त बनाना है। भारत को दया, सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर आधारित सॉफ्ट पावर की ज्यादा जरूरत है। नीता अंबानी ने इस बात पर भी जोर दिया कि लड़कियों को सशक्त बनाने से अंततः देश मजबूत होगा।

भिण्ड के लहार में लाइली बहना योजना का हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम

महिला सशक्तिकरण में लाइली बहना योजना कांतिकारी पहल: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिलाएं परिवार की रीढ़ और इज्जत होती हैं। सनातन संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिये प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहनों को सशक्त बनाना अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। वे चाहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएं प्रमुख भूमिका में रहें। महिला कल्याण और सशक्तिकरण की यही नीति मध्यप्रदेश सरकार की भी है। प्रदेश की लाइली बहना योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव परिवार को भिड़ जिले के लहार में लाइली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाइली बहनों को लाइली बहना योजना की 38वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि अंतिरित कर संबोधित कर रहे थे।

बहनों, बेटियों के विकास के साथ सभी नागरिकों के कल्याण के हो रहे कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की समृद्धि, सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। बहनों और बेटियों के साथ युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे नौकरी पाने में नहीं, बल्कि नौकरी प्रदान करने में सक्षम बनें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कतिपय लोग महिला कल्याण कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों ने स्वयं तो कभी भी लाइली बहना जैसी कारगर योजना प्रारंभ नहीं की, अब वे निंदा के अलावा कुछ नहीं करते। यह सर्वविदित है कि लाइली बहना योजना में बहनों को दी जा रही राशि परिवार में खुशियां लाने का माध्यम बनी हैं। हमारी बहनें लक्ष्मी, सरस्वती और जगदम्बा का स्वरूप हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ रहा है।



बहनों को सशक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भिंड जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भिण्ड का जवान सीमा की रक्षा करता है और किसान खेती से अपनी पहचान बनाता है। इस अंचल का संबंध महाभारत से जोड़ा जाता है। लहार नामकरण यहां लाक्षागृह के होने से हुआ, ऐसी मान्यता है। इस अंचल पर हनुमान जी की भी विशेष कृपा है। भिंड जिले के साहसी जवान भारतीय सेना में बड़ी संख्या में शामिल हैं। भिंड के बीहड़ कभी दस्यु समस्या के कारण जाने जाते थे, अब यह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। शिवपुरी जिले में हाल ही में सैन्य क्षेत्र में उपयोगी लंबी दूरी तक तेज मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल की इकाई प्रारंभ करने की पहल हुई है। चंबल, ग्वालियर क्षेत्र में समग्र प्रगति के प्रयास हो रहे हैं। यहां विकास को नए आयाम मिलेंगे। सांदीपनि विद्यालयों से विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ मिल रहे हैं संस्कार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भिंड जिले के जिन विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है, उनमें 4 सांदीपनि विद्यालयों की सौगात भी शामिल है। इतिहास गवाह है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मैत्री का उदाहरण सांदीपनि आश्रम था, अतः राज्य शासन ने सांदीपनि विद्यालय का नाम देकर विद्यार्थियों को समानता के महत्व से भी अवगत करवाया है।

मोदी बोले- मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया: यहीं मुझे गिफ्ट मिला था

हमारे लिए देश की जनसंख्या नहीं, उनकी भावना मायने रखती है

ऑकलैंड। पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने करीब तीन दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा- 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 टीशर्टें दीं, जो मैं भारत लेकर गया। एक- मफलर, दूसरी- कैप और तीसरा- एक सेट दस्ताना। उसमें मैं एक टीशर्ट मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है।



भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य जुड़ा है

ये कोलेब का जमाना है, दोनों देश साथ-अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में बात करें तो ये कोलेब का जमाना है। दोनों देश स्पोर्ट्स में भी बहुत शानदार कोलेब कर सकते हैं। रब्बी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत रब्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है।

हजारों किमी की दूरी, मगर दिल में हिंदुस्तान

हजारों किमी की दूरी, मगर दिल में हिंदुस्तान हजारों किमी दूर रहते हुए भी आपके दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं हिंदुस्तान बसता ही है। शरीर यहां होगा मन भारत में होगा। इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण भावना अहम-हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। यह वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था।

भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल दे रहा है

पीएम ने कहा- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल दे रहा है। यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकांनोमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत जितना फोकस इकांलोजी और इकांनोमी पर देता है उतना ही हैरिटेज पर भी देता है। हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा साहसा और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर कोने में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है।

एनालिसिस

दिल्ली सहित पांच राज्य वर्ल्ड बैंक की अपर-मिडल-इनकम कैटेगरी में पहुंचे, बिहार सबसे गरीब राज्य

भारत अभी भी बना हुआ है लोअर-मिडिल इनकम देश

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत अभी भी वर्ल्ड बैंक की नजर में लोअर-मिडिल इनकम वाला देश है, लेकिन देश के कुछ राज्यों की आर्थिक तस्वीर इससे कहीं बेहतर है। एक एनालिसिस के मुताबिक, भारत के 5 राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक की अपर-मिडिल इनकम की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस को उनकी आय में लगातार सुधार के चलते हाई इनकम ग्रुप में अपग्रेड किया है, जबकि भारत की प्रकृष्टि इनकम अभी भी 2,760 डॉलर के साथ लोअर-मिडिल इनकम कैटेगरी में बनी हुई है। हालांकि, राज्यों के स्तर पर तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत की प्रति व्यक्ति आय फिलहाल 2,760 डॉलर है। यह



महाराष्ट्र, हरियाणा व केरल मामूली अंतर से पीछे

महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 4,628 डॉलर रही, जो तय लिमिट से सिर्फ 8 डॉलर कम है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 4,627 डॉलर रही, यानी वह केवल 9 डॉलर से पीछे रह गया। वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय 4,610 डॉलर रही, जो इस लिमिट से 26 डॉलर कम है। यानी ये तीनों राज्य भी अपर-मिडिल इनकम कैटेगरी के काफी करीब पहुंच चुके हैं।

लोअर-मिडिल इनकम देशों के औसत 2,488 डॉलर से थोड़ा ही ज्यादा है। वहीं, अपर-मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति आय 4,636 डॉलर होनी चाहिए। यानी भारत अभी भी इस स्तर से काफी नीचे है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड बैंक की ओर से तय अपर-मिडिल इनकम की लिमिट से ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें दिल्ली सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति आय 6,217 डॉलर है। इसके बाद कर्नाटक (5,579 डॉलर), तेलंगाना (5,407 डॉलर), तमिलनाडु (5,329 डॉलर) और गुजरात (4,734 डॉलर) का स्थान है। इन सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 4,636 डॉलर की लिमिट से ज्यादा है।

तीन बड़े राज्य इस लिस्ट में शामिल होने से बहुत कम अंतर से चुक गए। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 4,628 डॉलर रही, जो तय लिमिट से सिर्फ 8 डॉलर कम है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 4,627 डॉलर रही, यानी वह केवल 9 डॉलर से पीछे रह गया। वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय 4,610 डॉलर रही, जो इस लिमिट से 26 डॉलर कम है। यानी ये तीनों राज्य भी अपर-मिडिल इनकम कैटेगरी के काफी करीब पहुंच चुके हैं।

यूपी और झारखंड भी काफी पीछे

रिपोर्ट के अनुसार, बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब बड़ा राज्य बना हुआ है। यहां प्रति व्यक्ति आय केवल 984 डॉलर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,403 डॉलर और झारखंड की 1,470 डॉलर है। एनालिसिस में कहा गया है कि इन तीनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय नेपाल और अफ्रीका के कई देशों से भी कम है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 30 सालों में मीडियम इनकम वाले राज्यों ने सबसे तेज आर्थिक ग्रोथ दर्ज किया। इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 1994-95 की तुलना में 36.7 गुना बढ़ी। वहीं सबसे समृद्ध राज्यों में यह ग्रोथ 28.3 गुना और सबसे गरीब राज्यों में 26.6 गुना रही। इस दौरान कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने सबसे तेज प्रगति की।

ओमान के पास जहाज पर हमला

11 भारतीय सवार थे,भारत ने हमले की निंदा की

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज जीएफएस गैलेक्सी एए हमला हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को बताया कि इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट में भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ मिलकर लापता भारतीय की तलाश और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत ने इस अभियान में सहयोग के लिए ओमानी अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया। भारत ने कहा कि क्षेत्र में व्यापारी जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। साथ ही तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बिना किसी बाधा के जहाजों की आवाजाही जल्द बहाल होनी चाहिए।



भारत ने ओमान के पास जहाज पर हमले की निंदा की

भारत ने ओमान तट के पास व्यापारी जहाज जीएएसएफ गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। रुद्ध ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ मिलकर सर्व ऑपरेशन पर नजर रखे हुए है। भारत ने नागरिक जहाजों पर हमले रोकने, तनाव कम करने और क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने की अपील की है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही बहाल करने की भी मांग की है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ओमान भी इसकी चपेट में आ गया है। ओमानी सरकार ने पुष्टि की है कि देश के मुसंदम गवर्नर में ड्रोन हमले हुए हैं।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर बोले-

पिता की मौत का बदला लेंगे

अली खामेनेई के निधन के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने पिता और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका खुद रूख का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि समझौता तभी चलेगा, जब दोनों पक्ष उसका पालन करें। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की, तो अमेरिका हजारों मिसाइलों से जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले ट्रेन में खालिस्तानी नारे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने जारी किया है। वीडियो में दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन के डिब्बों पर खालिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं। एसएफजे के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर पंजाब में आतंकवाद के दौर के मानवधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कथित एनकाउंटर मामलों को उठाया। हालांकि, टीम पन्नू के वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी किया

खालड़ा ने अज्ञात लाशों का ब्यौरा एकत्रित किया था- खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि 90 के दशक में शहीद खालड़ा ने अज्ञात लाशों का ब्यौरा एकत्रित किया था। ये लोग सिख युवा, बुजुर्ग, महिलाएं थे और इनको अज्ञात कहकर मार दिया गया था। जसवंत सिंह खालड़ा उनकी बात की थी। वह दौर था



सिख नरसंहार का। पन्नू ने मोदी को हिंदुस्तान का आतंकवादी कहा- पन्नू ने कहा ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान का आतंकवादी कहा। उसने कहा कि पंजाब में अब आर्थिक नरसंहार किया जा रहा है।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरीकरण माह का शुभारंभ, जागरूकता रैली निकाली गई



नीमच। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण माह के शुभारंभ पर जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

रैली को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ.आर.के. खद्योत, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेंद्र पाटील तथा डॉ.संगीता भारती ने जिला चिकित्सालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. आर.के. खद्योत ने बताया कि जिले में 11 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक जनसंख्या स्थिरीकरण

सेवा प्रदायगी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में नसबंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा परिवार नियोजन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए विभिन्न परिवार नियोजन साधन बास्केट ऑफ चॉइस के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें निरोध, माला-डी, माला-एन, छाया गर्भनिरोधक गोली, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोलियां तथा अंतरा इंजेक्शन शामिल हैं। हितग्राही अपनी आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी अस्थायी साधन का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महिला

एवं पुरुष नसबंदी की स्थायी सेवाएं भी जिले में निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पात्र हितग्राही शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेकर परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।

जागरूकता रैली जिला चिकित्सालय नीमच से प्रारंभ होकर फर्रुट मार्केट, हेमू कालानी चौराहा एवं सिंधी कॉलोनी मार्ग से होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पहुंचकर सम्पन्न हुई। रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शहरी आशा कार्यकर्ता तथा ज्ञानोदय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं ने हाथों में जागरूकता संबंधी तस्वियां लेकर सीमित परिवार के लाभों का संदेश दिया तथा नारों के माध्यम से आमजन को परिवार नियोजन एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग के मित्र श्री कमलालशर्मा कारपेंटर एवं श्री देवीलाल वर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले में अब तक औसत 258.2 मि.मी. वर्षा दर्ज

नीमच। जिले में चालू वर्षाकाल के दौरान अब तक औसत 258.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसत 315.1 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख, नीमच से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से 11 जुलाई 2026 की प्रातः 8 बजे तक जिले की चारों तहसीलों में वर्षा का विवरण इस प्रकार है- नीमच में 333.0 मि.मी., जावद में 239.0 मि.मी., सिंगोली में 240.9 मि.मी. तथा मनासा में 220.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

गत वर्ष इसी अवधि में नीमच में 293.6 मि.मी., जावद में 330.0 मि.मी., सिंगोली में 437.0 मि.मी. तथा मनासा में 200.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। इसी प्रकार, 11 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे तक बीते 24 घंटों में जिले में औसतन वर्षा रिकॉर्ड नहीं की गई। इस दौरान नीमच, जावद, मनासा एवं सिंगोली में वर्षा दर्ज नहीं की गई।



विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य संस्थाओं में आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम



देवास। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 18 जुलाई 2026 तक विश्व जनसंख्या दिवस अभियान संचालित किया जा रहा। अभियान के तहत आमजन को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय उम्मीदपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष की थीम ‘‘हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन प्रेनेसीज फार वेल बोइंग

ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड टु प्रिवेंट अनइन्टेन्ड प्रेनेसीज’’ (माँ और बच्चे के कल्याण तथा अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ समय और अंतर) है।

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. शाहिद शेख ने बताया कि अभियान के दौरान जिले का स्वास्थ्य अमला घर-घर पहुंचकर आमजन से संवाद स्थापित करेगा तथा परिवार नियोजन के आधुनिक, सुरक्षित एवं प्रभावी साधनों की जानकारी देकर उन्हें अपनी

खुशियों की दास्तां - वीबी जी राम जी योजना से अब गांव में ही मिलेगा ज्यादा काम, बड़ेगी आमदनी

सीहोरा। ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ङ्क डूङ्कल ऋत योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब प्रा ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक दैनिक मिलेगी। साथ ही, देश के किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी 2300 से कम नहीं होगी, जबकि राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर लगभग 327 प्रतिदिन हो गई है।

सीहोरा जिले की भैरूदा तहसील के ग्राम महागांव जदीद निवासी श्रीमती कृष्णा कीर कहती हैं कि पहले रोजगार के केवल 100 दिन मिलते थे, लेकिन अब 125 दिनों तक काम मिलने से परिवार की आय में बड़ोत्तरी होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी।

श्रीमती कृष्णा कीर ने कहा, ‘‘यह योजना हम जैसे ग्रामीण और मजदूर परिवारों के लिए बहुत लाभकारी है। अब गांव के आसपास ही ज्यादा दिनों तक काम मिलेगा, जिससे बाहर मजदूरी के लिए कम जाना पड़ेगा। रोजाना कम से कम 300 रुपये की मजदूरी मिलने से परिवार का खर्च चलाना आसान होगा और बच्चों की पढ़ाई सहित अन्य जरूरतें भी बेहतर तरीके से प्रबंधित की जा सकेंगी।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, ‘‘न्याय केवल न्यायालयों में नहीं मिलता अनेक बार वह समाज के भीतर संवाद विधायक और सहभागिता से भी स्थापित होता है। यदि प्रत्येक समुदाय में प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध हो तो अनेक विवाद प्रारंभिक स्तर पर ही शांतिपूर्वक सुलझाये जा सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि विकसित करना है जो विवाद को संघर्ष नहीं, बल्कि



संवाद और सहयोग का अवसर समझे। यह प्रशिक्षण केवल ज्ञान अर्जित करने का अवसर नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व स्वीकार करने का अवसर भी है।

प्रधान न्यायाधीश कृदुब् न्यायालय श्री वैभव मंडलोई ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि विवादों का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान करने के उद्देश्य

सफलता की कहानी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनी नीमच की अंतिमबाला के परिवार की आर्थिक संबल

नीमच। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके परिवार की खुशहाली का भी आधार बन रही है। योजना के तहत प्राप्त होने वाली नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ बच्चों की शिक्षा और परिवार के दैनिक खर्चों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसी क्रम में नीमच नगर के वार्ड क्रमांक-1 की निवासी श्रीमती अंतिमबाला कुमावत भी योजना से लाभान्वित हो रही हैं।

उन्हें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। अंतिमबाला बताती हैं कि योजना से मिलने वाली इस राशि का उपयोग वे अपने बच्चों की दृशान फीस, पढ़ाई-लिखाई एवं



अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं पर करती हैं। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और बच्चों की शिक्षा नियमित रूप से जारी रखने में सहायता मिली है। अंतिमबाला का कहना है कि पहले बच्चों की पढ़ाई का खर्च जुटाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता था, लेकिन अब हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें काफी राहत मिली है।

तीन दिवसीय ‘‘कम्युनिटी मीडिएशन’’ प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ



देवास। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा 20 घंटे के विशेष ‘‘कम्युनिटी मीडिएशन’’ (सामुदायिक मध्यस्थता) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 से 13 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विभिन्न समाजों में उनके परिचित सामुदायिक मध्यस्थों को तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। मुख्य प्रशिक्षक एम.सी.पी.सी. की सीनियर ट्रेनर सुश्री रीमा भण्डारी (दिल्ली) एवं एसोसिएट ट्रेनर के रूप में डॉ. मोहम्मद शमीम सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विभिन्न समाजों के गणमान्य प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रतिभागीगण को संघर्ष की प्रकृति एवं कारण, संघर्ष प्रबंधन, मध्यस्थता की परिभाषा और अवधारणा, मध्यस्थता प्रक्रिया और उसके चरण संचार कौशल, समझौता वार्ता, गतिरोध समाप्त करने की तकनीक, समझौता लेखन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार होने वाले मध्यस्थ भविष्य में स्थानीय और सामुदायिक स्तर के विवादों को न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित, जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

सीहोरा। विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा किशोर स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम सीहोरा जिला अस्पताल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

जिला अस्पताल में दृक्कः के सहयोग से प्रचार प्रसार के लिए सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही रैली के माध्यम से आमजन को विवाह के बाद प्रथम संतान में उचित अंतराल रखने, दो बच्चों के जन्म के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतर रखने, प्रसवोत्तर एवं गर्भपातोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ लेने, पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता बढ़ाने तथा दीर्घकालिक एवं अस्थायी गर्भनिरोधक साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई।

सीएमएचओ डॉ॰ सुधीर डेहरिया ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा किशोर स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता के लिए जिले में 11 से 18 जुलाई तक अभियान का चलाया जा रहा है। अभियान की थीम ‘‘Healthy Timing & Spacing Between Pregnancies for well-being of mother & child and to prevent unintended pregnancies’’ है, जिसका संदेश है कि ंमाँ और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए गर्भधारण का सही समय तथा गर्भावस्थाओं के बीच उचित अंतर रखना आवश्यक है तथा अनचाहे गर्भधारण से बचना चाहिए।

ई-लोक अदालत में करारा गया 14

प्रकरणों में समझौता

सीहोरा । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई-लोक अदालत में सीहोरा जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 09 खण्डपीठों का गठन किया गया। ई-लोक अदालत में कुल 45 प्रकरण रखे गये 14 प्रकरणों का निराकरण कर समझौता राशि 53 लाख 69 हजार 593 रुपये प्राप्त हुई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा ई-लोक अदालत लगाये जाने के निर्देश के पालन में जिला सीहोरा में पहल की गई तथा ई-लोक अदालत में पक्षकारों को न्यायालय तक ना आना पड़े इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर पक्षकारों से आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से कुल 14 प्रकरणों में समझौता करवाया गया।

रतलाम। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने नौ राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावद, तहसीलदार सैलाना, तहसीलदार रावटी, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग), तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा अलोट, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ तथा न्यायालय नायब तहसीलदार

पिपलौदा के कुल 38 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावद श्री भगवान सिंह ठाकुर पर 04 लॉबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार सैलाना श्री कुलभूषण शर्मा पर 01 लॉबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, तहसीलदार रावटी श्रीमती वंदना किराडे पर 01 लॉबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग) श्री ऋध्र ठाकुर पर 04

प्रधानमंत्री आवास समाधान शिविर 13 से 17 जुलाई तक जनपद पंचायत कार्यालयों में आयोजित होंगे

रतलाम। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्रधानमंत्री आवास शिविर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक सभी जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की लॉबित समस्याओं का त्वरित समाधान, जिन हितग्राहियों की आवास की रुकी हुई किस्त, दस्तावेजों में त्रुटि, आधार त्रुटि सुधार, बैंक खाते या डिबीटी से संबंधित समस्या, समग्र आईडी एवं पोर्टल से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।

जिले के सभी पत्र नागरिकों से अनुरोध है कि शिविर में आते समय सप्ताग परिवार आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अवश्य साथ लेकर आएँ।

रतलाम जिले की सभी तहसीलों में शनिवार को आयोजित होंगे राजस्व निराकरण शिविर-कलेक्टर श्रीमती सिंह

रतलाम । कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशन में जिले की सभी तहसीलों में आज शनिवार को राजस्व निराकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करना है।

शिविरों में सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेखों में त्रुटि सुधार तथा अन्य राजस्व संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि जिनके राजस्व संबंधी प्रकरण लॉबित हैं अथवा किसी प्रकार की समस्या है, वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसील कार्यालय में आयोजित राजस्व निराकरण शिविर में उपस्थित होकर शासन की इस सुविधा का लाभ उठाएं।



उच्च शिक्षा में कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, कौशल निर्माण और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलते रोजगार बाजार ने शिक्षा की भूमिका को व्यापक बना दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव और आधुनिक कौशल भी प्रदान किए जाएँ।



कौशल आधारित शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने कौशल आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। इसका उद्देश्य

विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। वर्तमान उद्योग जगत ऐसे युवाओं की अपेक्षा करता है जिनमें तकनीकी ज्ञान के साथ संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, टीम भावना और नवाचार की सोच भी

विद्यार्थियों को प्रति स्पर्धात्मक वातावरण में सफल बनाते हैं।

आधुनिक तकनीक और नए अवसर

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ई-कॉमर्स तथा स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं। यदि उच्च शिक्षण संस्थान इन विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें, तो विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का लाभ उठा पाएँगे।

नैतिक मूल्यों का समावेश

उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना भी है। शिक्षा तभी सार्थक मानी जाएगी, जब वह विद्यार्थियों को योग्य पेशेवर के साथ-साथ संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाए।

डॉ. नीलेश पाण्डेय प्राचार्य हितकारिणी महिला महाविद्यालय, जबलपुर



रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को इंटरनशिप, परियोजना कार्य, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा डिजिटल साक्षरता से जोड़ना समय की मांग है। इससे उन्हें वास्तविक कार्य-परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त होता है और रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। विशेष रूप से छात्राओं के लिए कौशल आधारित शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है।

12वीं के बाद करियर में चाहिए हाई सैलरी और शानदार ग्रोथ? पेट्रोलियम इंजीनियर बनकर संवारेँ अपना भविष्य

12वीं साइंस स्ट्रीम (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स) से पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने अक्सर इंजीनियरिंग के पारंपरिक विकल्प ही आते हैं। लेकिन यदि आप लीक से हटकर एक ऐसे करियर की तलाश में हैं, जिसमें शुरुआत से ही शानदार सैलरी पैकेज और बेहतरीन करियर ग्रोथ मिले, तो पेट्रोलियम इंजीनियर आपके लिए सबसे बेहतरीन और हाई-पेइंग विकल्पों में से एक साबित हो सकता है।

क्या होता है एक पेट्रोलियम इंजीनियर का काम?

पेट्रोलियम इंजीनियर का मुख्य काम जमीन के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडारों की पहचान करना, उनका सुरक्षित उत्पादन बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों की मदद से इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होता है। इसके तहत कार्य प्रकृति के आधार पर कई विशेष प्रोफाइल होते हैं।

1 **रिजवायर इंजीनियर**— इनका काम आधुनिक तकनीकों से जमीन के नीचे के भंडारों का विश्लेषण करना होता है।

सरल शब्दों में, ये पता लगते हैं कि किस स्थान पर कितना तेल या गैस मौजूद है।

2 **अड्रिलिंग इंजीनियर**— तेल और गैस को सुरक्षित तरीके से जमीन से बाहर निकालने के लिए पूरी प्लानिंग, डिजाइनिंग और ड्रिलिंग प्रक्रिया को अंजाम देना इनका काम होता है।

3 **अप्रोडक्शन इंजीनियर**— कुओं से तेल और गैस का प्रवाह सही बनाए रखना, उत्पादन की लागत को प्रबंधित करना और उपयोग होने वाले भारी उपकरणों को निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी होती है।



एक्जीक्यूटिव एमबीए क्या है और क्यों बन रहा है

वर्किंग प्रोफेशनल्स की पहली पसंद?

आज के बदलते और कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है जिन्हें काम का अच्छा-खासा एक्सपीरिएंस है उनके बीच एक्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री पहली पसंद बन रही है। इस कोर्स की खास बात यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिना नौकरी छोड़े बिजनेस की नई स्किल्स, स्ट्रेटेजिक सोच और प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने में मदद करता है। इस कोर्स को करने वाले करीब 97 प्रतिशत स्टूडेंट्स के पास 13 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस होता है, जिससे क्लासरूम में चर्चा और नेटवर्किंग का लेवल बहुत शानदार हो जाता है। इसके अलावा और क्या कुछ खास है इस कोर्स के बारे में आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में...

एक्जीक्यूटिव एमबीए के फायदे

इंटरनेशनल बिजनेस स्किल्स

आजकल ऑनलाइन और हाइब्रिड यानी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पढ़ाई की बड़ी पहचान मिल रही है। अब प्रोफेशनल्स ट्रेवल करते हुए या दूरदराज के इलाकों से भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। कई बड़े बिजनेस स्कूल अब एशियन संस्थानों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल बिजनेस के तौर-तरीकों को सीधे समझने और ग्लोबल एक्सपोजर पाने का मौका मिल रहा है।

नेटवर्किंग होती है मजबूत

इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है शानदार नेटवर्क। यहां इक्सपीरिएंस फैकल्टी, गेस्ट स्पीकर्स और अलग-अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स एक साथ आते हैं। यह मजबूत एलुमनाई नेटवर्क



आगे चलकर नए बिजनेस पार्टनर्स, जॉब ऑफर्स और स्टार्टअप शुरू करने में बहुत मददगार साबित होता है।

फुल-टाइम एमबीए से बेहतर

इसमें आपको अपनी चलती हुई नौकरी या सैलरी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आपको कमाई बंद नहीं

होती, इसलिए इस कोर्स पर होने वाला खर्च जेब पर भारी नहीं पड़ता। इसलिए यह फुल-टाइम एमबीए से कहीं बेहतर होता है। इसकी पढ़ाई केस स्टडीज और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर आधारित होती है, यानी वीडेड पर आपने जो सीखा, सोमवार को उसे सीधे अपने ऑफिस के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर

कोई बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या वकील है, तो जरूरी नहीं कि उसे बिजनेस चलाना या टीम संभालना भी आता हो। ई एमबीए ऐसे ही टैक्निकल एक्सपर्ट्स को फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी की भाषा सिखाता है।

सीवी होती है मजबूत

इसके बाद वे आसानी से कंपनी के बड़े पदों, जैसे सीईओ, सीएफओ पर बैठने के काबिल बन जाते हैं। इसके साथ ही, कोर्स के दौरान मिलने वाली पर्सनल करियर कोचिंग आपको सीवी बेहतर करने और इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करती है। आसान शब्दों में कहें तो, साल 2026 के अनिश्चित बाजार में ई एमबीए प्रोफेशनल्स को करियर में लंबी छलांग लगाने का सबसे मजबूत जरिया बन गया।

नेटवर्किंग बनाम मेंटरशिप

उज्ज्वल भविष्य के लिए कौन है अधिक महत्वपूर्ण?



आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल डिग्री या तकनीकी ज्ञान ही सफलता की गारंटी नहीं है। करियर में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों से जुड़ना और अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि नेटवर्किंग और मेंटरशिप आज हर क्षेत्र में सफलता के दो महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। अक्सर युवाओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि बेहतर भविष्य के लिए इनमें से कौन अधिक उपयोगी है। वास्तव में, दोनों की अपनी अलग भूमिका है और दोनों मिलकर व्यक्ति के करियर को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं।

नेटवर्किंग क्या है?

नेटवर्किंग का अर्थ है अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों, सहकर्मियों, शिक्षकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य पेशेवरों से सकारात्मक संबंध स्थापित करना। यह केवल परिचय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और अवसरों का आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया भी है।

नेटवर्किंग के प्रमुख लाभ

- ▶ रोजगार और करियर के नए अवसर प्राप्त होते हैं।
- ▶ विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी और रुझानों से परिचित होने का अवसर मिलता है।
- ▶ व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए नए साझेदार एवं ग्राहक मिल सकते हैं।
- ▶ आत्मविश्वास, संवाद कौशल और व्यक्तित्व का विकास होता है।
- ▶ कठिन परिस्थितियों में अनुभवी लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

जर्मनी में मास्टर्स के लिए देना होगा डीमेट एग्जाम, कैसे करें तैयारी

जर्मनी में हायर एजुकेशन हासिल करने की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स को यहां एडमिशन के लिए जरूरी सभी एग्जाम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। हाल ही में जर्मनी में डीमेट नाम का एक और एग्जाम लाया गया है। आज हम इसी एग्जाम की तैयारियों के बारे में जानेंगे

डीमेट एग्जाम टिप्स

वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटीज, किफायती ट्यूशन फीस और बढ़िया करियर अवसर मुहैया कराने की वजह से जर्मनी, भारतीय छात्रों के बीच एक पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल हजारों भारतीय यहां मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से एडमिशन को लेकर कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए अब एक नया एग्जाम लाया गया है, जो मास्टर्स एडमिशन के लिए जरूरी होगा।

जर्मनी की एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत एक नया डिजिटल मास्टर असेसमेंट टेस्ट यानि डीमेट अनिवार्य किया जा रहा है। अगर आप 2027 में जर्मनी में एडमिशन



लेना चाहते हैं, तो अब आपको यह एग्जाम देना होगा, जो एपीएस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी किस तरह करनी होगी और ये एग्जाम किसके लिए है।

डीमेट एग्जाम क्या है?

यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो कुछ खास मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके जरिए स्टूडेंट की बौद्धिक क्षमता, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट को लेकर उसकी जानकारी को

एग्जाम का पैटर्न कैसा है?

इस एग्जाम को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला कोर मांड्यूल और दूसरा सब्जेक्ट मांड्यूल हैं। कोर मांड्यूल के जरिए स्टूडेंट की सामान्य अध्ययन क्षमता और सज्ञानात्मक (कॉग्निटिव) स्किल को चेक किया जाता है। कोर मांड्यूल मुख्य तौर पर तीन सब-टेस्ट में बांटा गया है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव स्किल शामिल हैं। सब्जेक्ट मांड्यूल के जरिए देखा जाता है कि स्टूडेंट ने पिछली पढ़ाई के दौरान जो नॉलेज हासिल की थी, उसके जरिए वह समस्याओं को किस तरह सुलझा सकता है। यह साढ़े तीन घंटे तक चलने वाली परीक्षा है, जिसमें दोनों मांड्यूल के बीच में एक ब्रेक भी दिया जाएगा। एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब सिंगल-चॉइस फॉर्मेट में होंगे और ये परीक्षा अंग्रेजी में होगी।

डीमेट एग्जाम किसे देना है?

एग्जाम जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हर स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से जुड़ा मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं।

ज्ञान प्रभा स्कॉलरशिप योजना

दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता



ज्ञान प्रभा स्कॉलरशिप योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो बौद्धिक एवं बहु-दिव्यांगता से प्रभावित हैं।

योजना का उद्देश्य

- ▶ दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- ▶ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता करना।
- ▶ कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- ▶ शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।

किन छात्रों को लाभ मिलता है?

यह योजना निम्न दिव्यांगताओं से प्रभावित छात्रों के लिए है

- 1 ऑटिज्म
- 2 सेरेब्रल पाल्सी
- 3 बौद्धिक दिव्यांगता
- 4 बहु-दिव्यांगता

पात्रता

- ▶ आवेदक भारत का नागरिक हो।
- ▶ राष्ट्रीय ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत दिव्यांगता हो।
- ▶ मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज या कौशल विकास संस्थान में अध्ययनरत हो।
- ▶ आवश्यक दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध हों।

आवश्यक दस्तावेज

- ▶ आधार कार्ड
- ▶ दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- ▶ आय प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
- ▶ बैंक पासबुक
- ▶ पासपोर्ट आकार फोटो
- ▶ शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- ▶ संस्थान का प्रवेश प्रमाणपत्र

आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। ज्ञान प्रभा स्कॉलरशिप स्कीम का चयन करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा कर उसकी रसीद सुरक्षित रखें।

[फीफा विश्व कप 2026] विश्वकप के इतिहास में तीसरी बार अंतिम चार में जगह बनाई

बेल्जियम को 2-1 से हराकर स्पेन सेमीफाइनल में पहुंचा

एजेंसी ■ इंग्लवुड, (कैलिफोर्निया)

सुपर-सब मिकेल मेरिनो के आखिरी क्षणों में किए गए गोल की बदौलत स्पेन ने फीफा विश्वकप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम पर 2-1 से जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह विश्वकप के इतिहास में तीसरी बार है जब स्पेन ने अंतिम चार में जगह बनाई है।

लॉस एंजेलिस स्टेडियम में शुरुवार रात खेले गए विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में स्पेन की ओर से फैबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए। वहीं बेल्जियम की ओर एकमात्र गोल चार्ल्स डी केटेलेरे ने दागा। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ गोल दागे। स्पेन की ओर से फैबियन रुइज ने 30वें मिनट में गोलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद 11 मिनट बाद बेल्जियम ने चार्ल्स डी केटेलेरे के

41वें मिनट के गोलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

ऐसे में मैच जब अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, इसी दौरान बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कोर्टुआ चोट के कारण 71वें मिनट में मैदान से बाहर चले गए। उनके स्थान पर आए सेन लामेंस 88वें मिनट में मिकेल मेरिनो के गोल को नहीं रोक पाए। इस निर्णायक गोल ने स्पेन को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा किया और इटली के 37 मैचों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया। स्पेन अब मंगलवार को एक सपने जैसे सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना करेगा। पिछले तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच यह तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें स्पेन ने 2024 में यूरोपीय चैंपियनशिप और 2025 में यूईएफए नेशंस लीग के सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी।



हम फ्रांस को हरा सकते हैं, हम पूरी मेहनत करेंगे-फुएंते

बेल्जियम पर जीत के बाद स्पेन के मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा, 'यह हमारी टीम के जज्बे का परिणाम है। इतनी समर्पित और लगातार बेहतर करने वाली टीम का कोच होना मेरे लिए सम्मान की बात है। हम फ्रांस को हरा सकते हैं। हम इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमारी टीम दो बार फ्रांस को हरा चुकी है। अब एक महान टीम का सामना दूसरी महान टीम से होगा।

मैच विजयी गोल करने वाले मिकेल मेरिनो ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूँ। शायद ऐसा मौका दोबारा कभी न मिले। हम विश्वकप



जीतने से सिर्फ दो मैच दूर हैं। यह सपना सच होने जैसा है। उम्मीद है कि हम इसे पूरा करेंगे।'



एमबाप्पे बनाम यमाल पर भी होगी नजर

सेमीफाइनल में फुटबॉल प्रेमियों की नजर किलियन एमबाप्पे और लामिन यमाल की भिड़त पर भी रहेगी। एमबाप्पे इस विश्व कप में पांच मैचों में आठ गोल और तीन असिस्ट के साथ शानदार फॉर्म में हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में

लियोनेल मेसी के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। वहीं यमाल अपनी ड्रिब्लिंग, गति और शानदार पासिंग से स्पेन के सबसे बड़े खेमेकर बनकर उभरे हैं। हालांकि, यमाल का कहना है कि बड़े नामों से स्पेन पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा।

सेमीफाइनल के लिए अर्जेंटीना-स्विट्जरलैंड के बीच आज प्रातः होगा मुकाबला



नई दिल्ली। डिफेंसिव चैंपियन अर्जेंटीना 12 जुलाई यानी रविवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच कैनसस सिटी स्टेडियम में सुबह 6.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेगा।

भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया- गार्सिया

बेल्जियम फुटबॉल टीम के मुख्य कोच और मैनेजर रूडी गार्सिया ने स्पेन के हाथों विश्व कप क्वार्टर फाइनल में 2-1 से मिली हार को लेकर अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। मैच के बाद, गार्सिया ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, 'यह बहुत सरल था, हम अपने विश्व कप प्रदर्शन पर गर्व कर सकते हैं, हम सीखते हैं, हम हार से सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें शर्मिंदा होने की



कोई बात है। मुझे लगता है कि हम स्पेनिश टीम को कड़ी टक्कर देने में सक्षम थे। दुर्भाग्यवश, आज शाम किस्मत हमारे साथ नहीं थी। हमने अपना गोलकीपर खो दिया। हमने अपना कप्तान खो दिया। हमें डी ब्रुइन को दिए गए स्क्वैडिट्यूट को बदलना पड़ा, जो मैच के अंत में हमारी खेल योजना का हिस्सा नहीं था।'

ब्राजील के विश्व कप से बाहर होने पर विनीसियस ने मांगी माफी

रियो डी जेनेरो।

विनीसियस जूनियर ने नॉर्वे से राउंड ऑफ 16 में हारकर ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अपनी 'बेहद निराशा' जाहिर की है। 25 साल के खिलाड़ी ने पिछले रविवार को नॉर्वे से ब्राजील की 2-1 से हार के लिए फेन्स से माफी मांगी। यह नतीजा 1990 के बाद से टीम के वर्ल्ड कप से सबसे जल्दी बाहर होने का कारण बना। उन्होंने कहा, 'लगभग चार साल बाद, मैं

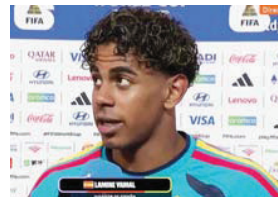


एक बार फिर सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की निराशा के बाद क्या लिखूँ, 'उन्होंने कतर में क्रोएशिया से क्वार्टर फाइनल में मिली हार का जिक्र करते हुए यह बात कही।' हर उम्र के बहुत से लोगों ने हमारा समर्थन किया और

हमारे सपने को अपनाया, इसलिए चुप रहना गलत होता। लेकिन मुझे सोचने-समझने के लिए कुछ दिनों की जरूरत थी।

सेमीफाइनल में फ्रांस को हमसे डरना चाहिए-लामिन यामल

स्पेन के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यामल ने कहा, हमने फ्रांस को पहले भी दो बार हराया और इसलिए फीफा विश्वकप के सेमीफाइनल में उन्हें हमसे डरना चाहिए। इंग्लेवुड स्थित सोफी स्टेडियम में बेल्जियम पर स्पेन की जीत के बाद यामल ने पत्रकारों से कहा, 'अगर फ्रांस को किसी से डरना चाहिए, तो वह हम हैं। हमने उन्हें पहले भी हराया है। हमने उन्हें दो बार मात दी है। सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि हम विश्व कप की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों हैं, इसलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमें



कोई डर नहीं है। यामल ने कहा, 'ऐसा लग सकता है कि हम अच्छे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम जिस भी टीम के खिलाफ खेलते हैं, वह हमारे खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाती है। किसी ने भी हमारा डटकर मुकाबला नहीं किया, लेकिन अंत में आज फिर से जीत हमारी ही हुई।

गेहूँ-चावल सस्ता, शकर महंगी, आटे की कीमतों में उछाल

नई दिल्ली। (एजेंसी)

घरेलू थोक जिस बाजारों में शनिवार को चावल का औसत भाव गिर गया। चावल के साथ गेहूँ और दालों में भी नरमी रही जबकि शकर मजबूत हुई है। खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 79 रुपये टूटकर 3,884 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूँ 12 रुपये सस्ता हुआ और 2,800 रुपये प्रति

दिल्ली थोक जिस बाजार भाव



क्विंटल बोला गया। आटे की कीमत 21 रुपये बढ़ गई।

दाल-दलहनों में मसूर दाल की औसत कीमत 61 रुपये प्रति



क्विंटल गिर गयी। चना दाल 37 रुपये और मूंग दाल 15 रुपये टूट गयी। उड़द दाल आठ रुपये और तुअर दाल चार रुपये प्रति क्विंटल

सस्ती हुई। स्थानीय बाजार में मूंगफली तेल की औसत कीमत 51 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी जबकि अन्य खाद्य तेलों में गिरावट रही। वनस्पति 65 रुपये और पाम ऑयल 51 रुपये सस्ता हुआ। सरसों तेल 46 रुपये और सोया तेल 10 रुपये फिसल गया। सूरजमुखी तेल तीन रुपये प्रति क्विंटल उतर गया। मीठे के बाजार में आज गुड़ का औसत भाव 16

रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया। चीनी भी 14 रुपये महंगी हुई। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे: दाल-दलहन: दाल चना 7758.83 रुपये, मसूर काली 8130.15 रुपये, मूंग दाल 10142.05 रुपये, उड़द दाल 11001.50 रुपये, तुअर दाल 11311.20 रुपये प्रति क्विंटल रही।

होम लोन में सिर्फ ईएमआई नहीं कुल ब्याज पर करें फोकस

एजेंसी ■ नई दिल्ली

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अक्सर लोग होम लोन लेते समय सिर्फ मासिक ईएमआई पर ध्यान देते हैं। यह जल्दबाजी बाद में महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि बैंक को चुकाई जाने वाली कुल रकम आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं

कि सिर्फ ईएमआई नहीं, बल्कि कुल ब्याज और लोन की अवधि को ध्यान में रखकर ही होम लोन का फैसला लेना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक बताते हैं कि 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेने पर मासिक ईएमआई भले ही करीब 43,390 रुपये लगे।

नीति आयोग ने की शांति अधिनियम के कार्यान्वयन पर परामर्श बैठक

नई दिल्ली। नीति आयोग ने अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ शुक्रवार को शांति अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों एवं प्रमुखों तथा नीति निर्माताओं ने अधिनियम के परिचालन तंत्र पर विचार-विमर्श किया। परामर्श बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर अभय करंदीकर ने की। बैठक के दूसरे भाग में हितधारकों ने अधिनियम के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु आवश्यक वित्तीय तंत्रों और जोखिम-निवारण ढांचों की समीक्षा की।

इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा बढ़ा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को जारी इन बैंकों के शेरों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। इंडियन बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 3,272 करोड़ रुपये रहा, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 27 फीसदी बढ़कर 2,020 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। शुक्रवार को जारी बेहतर तिमाही नतीजों के बाद

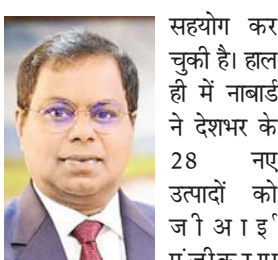


इंडियन बैंक के शेयर करीब 10 फीसदी चढ़कर बीएसई में 870.95 रुपए पर बंद हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर भी करीब 3 फीसदी बढ़कर 84.35 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए। इंडियन बैंक की ब्याज से शुद्ध आमदनी 17 फीसदी बढ़कर 7,435 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ऋण वितरण सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 6.84 लाख करोड़ रुपए हो गया।

कंठी-माला व अलीगढ़ की मूर्तियों को मिला जीआई टैग, नाबार्ड ने किया सहयोग

लखनऊ। (एजेंसी)

बांके बिहारी की धरती मथुरा में बनने वाली कंठी माला सहित उत्तर प्रदेश के तीन नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) मिला है। इनमें अलीगढ़ में तैयार होने वाली धातु की मूर्तियां व दस्तगी-हस्तगी उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों को जीआई टैग दिलाने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाबार्ड ने इन जीआई उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न चैनल भागीदारों का सहयोग किया है। अब तक संस्था 176 उत्पादों को जीआई पंजीकरण प्राप्त कराने में



दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाले इन नए उत्पादों में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला तथा वाद्य यंत्रों सहित विविध श्रेणियाँ शामिल हैं। इससे भारत के क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के पोर्टफोलियो को कानूनी संरक्षण

मिलने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में उनकी संभावनाओं को भी और अधिक मजबूती मिली है। नाबार्ड अध्यक्ष के मुताबिक नए जीआई टैग वाले उत्पादों में अलीगढ़ के मेटल स्टैच्यू, दस्तगी-जो अ अ इ पंजीकरण मिलने के साथ ही बिहार की नालंदा बावनबूटी साड़ी एवं वस्त्र तथा गया पत्थरकट्टी शिल्प, झारखंड की कुचाई सिल्क साड़ी एवं वस्त्र, असम के बांस शिल्प और बिहू पेपा, हिमाचल प्रदेश का वुड कार्विंग शिल्प, तथा मध्य प्रदेश का खजुराहो धातु शिल्प सहित देशभर के कई अन्य पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं। नाबार्ड अध्यक्ष ने

50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए

डॉ. शाजी कृष्णन वी. ने कहा, 'नाबार्ड उत्पादों के सामूहिकीकरण, कौशल विकास, उद्यम संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार से जुड़ाव तथा निर्यात सुविधा के माध्यम से जीआई-आधारित मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत की विशिष्ट विरासत स्थायी आर्थिक अवसरों में परिवर्तित हो सके।' उन्होंने जानकारी दी कि नाबार्ड की जीआई-आधारित पहलों के

माध्यम से 13,000 से अधिक कारीगरों और उत्पादकों को उच्च-मूल्य वाले घरेलू बाजारों से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली है और पारंपरिक उत्पादों की व्यावसायिक संभावनाओं में वृद्धि हुई है। नाबार्ड द्वारा समर्थित जीआई मूल्य शृंखलाओं और उनसे जुड़े उद्यमों के माध्यम से अब तक 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और गुजरात में विभिन्न

भाजपा कार्यालय में देवड़ा ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया, जबकि शेष प्रकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव है, उनमें बिना विलंब कार्रवाई की जाए तथा अन्य मामलों का भी



समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा उनकी ओर से उठाए गए जनहित के मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल

भोपाल (नगर संवाददाता)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अगली बैठक मंगलवार के स्थान पर बुधवार को होगी। कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे होगी। आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

प्रदेश में अल्प बारिश की संभावित आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रियों से बांधों के पानी की उपयोगिता, फसल उत्पादन आदि पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः कैबिनेट की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने के चलते इस बार कैबिनेट बैठक एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। पिछले मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी।

नामांकन रद्द होने के मामले में चुनाव आयोग को बचाने और कांग्रेस को बदनाम करने झूठी कहानी गढ़ी गई : नटराजन

भोपाल (नगर संवाददाता)

राजधानी में सोमवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के मामले में पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नामांकन निरस्त होने के लिए कांग्रेस या उसके नेताओं की कोई गलती नहीं थी। दरअसल चुनाव आयोग को बचाने के लिए पार्टी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करेगी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विवाद पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने पहली बार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन



राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने मीडिया के सामने रखी अपनी बात

निरस्त होने के लिए कांग्रेस नेताओं, वकीलों या नामांकन प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई गलती नहीं थी। यह धारणा जानबूझकर बनाई गई कि पार्टी की लापरवाही के कारण नामांकन खारिज हुआ, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करेगी।

निरस्त होने के लिए कांग्रेस नेताओं, वकीलों या नामांकन प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई गलती नहीं थी। यह धारणा जानबूझकर बनाई गई कि पार्टी की लापरवाही के कारण नामांकन खारिज हुआ, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करेगी।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल: नटराजन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पूरे मामले में निष्पक्ष संस्था की भूमिका नहीं निभाई। उनका कहना था कि कांग्रेस नेताओं और वकीलों ने समय पर अपना पक्ष रखा, लेकिन आयोग ने राहत देने के बजाय रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा।

नामांकन रद्द करने के आधार पर उठाए सवाल

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने उनके खिलाफ लंबित प्रकरण की जानकारी नहीं देने को आधार बनाकर नामांकन खारिज किया, जबकि नामांकन के साथ जमा किए जाने वाले फॉर्म-26 में ऐसी जानकारी देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाद में संबंधित अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया कि उस मामले में न्यायालय ने सज्ञान तक नहीं लिया था। ऐसे में नामांकन निरस्त करने का आधार ही टिकाऊ नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधि विशेषज्ञों पर लापरवाही का आरोप पूरी तरह निराधार है। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारता वर्षों से चुनावी प्रक्रिया संभालते रहे हैं और ऐसी सामान्य त्रुटि की संभावना नहीं थी। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल न उठे, इसलिए पूरी कहानी कांग्रेस की गलती बताकर पेश की गई।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कुवैत की मत्स्य कंपनी ने किया 7,430 करोड़ का एग्रीमेंट

प्रदेश से 6 हजार करोड़ के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य, 35 हजार रोजगार सृजित होंगे

भोपाल (नगर संवाददाता)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाता की समृद्धि के लिए कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं विकसित हो रही हैं। प्रदेश के मछुआरा समुदाय के लोग मछली पालन के जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इन सबकी बेहतरी के लिए मप्र एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के अंतर्गत गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया जा रहा है। आज कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदास केयर इंदौर के बीच हुआ एग्रीमेंट प्रदेश में मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी- ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और कामदास केयर इंदौर के बीच प्रदेश में 7 हजार 430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यह



एग्रीमेंट मप्र एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सीएम हाउस में एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर के बाद यह विचार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए एग्रीमेंट के दौरान जानकारी दी गई कि मप्र एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 के अंतर्गत राज्य में आधुनिक निर्यातोन्मुखी एवं मूल्य संवर्धन मत्स्य उद्योग के

सीएम ने कहा- मप्र के के मछली उत्पादन को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान

विकास के लिए निजी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है। अनुबंध के अंतर्गत 7 हजार 430 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। केज कल्चर के जरिए लगभग 4 लाख टन का

विकास के लिए निजी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है। अनुबंध के अंतर्गत 7 हजार 430 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। केज कल्चर के जरिए लगभग 4 लाख टन का

अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। इसके साथ ही एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस से 1 लाख 23 हजार टन वैजिटेबल्स आदि का भी उत्पादन होगा। प्रदेश में हो रही इस नई पहल से 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य है। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के मछुआरे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुवैत हमारा मित्र देश है, प्रदेश में विदेशी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्पण के साथ तेजी से कार्य कर रही है, अब इसके सुखद परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। भविष्य में मप्र मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। यह अनुबंध मप्र को देश का अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केन्द्र बनाने की दिशा में एक प्रयास है।

समय-सीमा समीक्षा बैठक में की विभागवार की गई समीक्षा

सीएम हेलपलाइन की शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

टीएल बैठक में एडीएम सुमित पांडे ने जताई नाराजगी

भोपाल (नगर संवाददाता)

जिले में सीएम हेलपलाइन और जनसुनवाई की शिकायतों के समय पर निराकरण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा (टीएल) समीक्षा बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सुमित पांडे ने विभागवार समीक्षा के दौरान लंबित और अनटेन्डेड शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में



लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम ने कहा कि सीएम हेलपलाइन पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। केवल औपचारिक जवाब देकर

शिकायतों का निराकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों का जल्द समाधान कर शिकायतकर्ताओं को राहत दिलाई जाए।

बैठक में जनसुनवाई से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कई मामलों में कार्रवाई लंबित रहने

पर एडीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ तय समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को एक ही समस्या के समाधान के लिए बार-बार जनसुनवाई में न आना पड़े।

आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए विभागों को विधानसभा

प्रश्नों के सही और समय पर जवाब तैयार रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा कृषि विभाग को 'कृषक कल्याण वर्ष' के लक्ष्य पूरे करने, खनिज विभाग को अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाओं और अभियानों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी केंद्रों के को-लोकेशन की प्रक्रिया तेज करने, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और साक्षरता अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

बिजली कंपनी : जिस ठेकेदार के नाम कार्य आदेश, वही करेगा काम

सीएमडी ऋषि गर्ग ने जारी किए निर्देश

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि जिस पैनलबॉर्ड ठेकेदार के नाम पर कार्य आदेश जारी हुआ है, वही संबंधित कार्य करेगा। किसी भी स्थिति में ये कार्य किसी अन्य ठेकेदार, एजेंसी या व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकेगा। कंपनी ने लाइन एवं सबस्टेशन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने ये कदम उठाया है।

बता दें कि कंपनी के सज्ञान में



आया था कि कुछ स्थानों पर कार्य आदेश एक ठेकेदार के नाम पर जारी हुआ है, लेकिन काम किसी अन्य व्यक्ति या ठेकेदार से कराया जा रहा था। इसे कंपनी ने नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है। जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी तय करेंगे कि कार्य केवल अधिकृत ठेकेदार ही करेंगी। इसके लिए नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण भी किया जाएगा।

बिना काटे बिजली पहुंचाने का कीर्तिमान

आंधी-तूफान, तेज बारिश, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा और अन्य अप्रत्याशित व्यवधानों जैसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने उल्लेखनीय कीर्तिमान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनी को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि कंपनी की 593 एक्सटेंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों ने पिछले चार वर्षों से बिना बाधा के निबंध विद्युत आपूर्ति हो रही है।

कक्षा पांच-आठ की पुर्नपरीक्षा के परिणाम होंगे घोषित

दो लाख 49 हजार बच्चों ने दी परीक्षा

विद्यार्थी राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल पर परिणाम देख सकेंगे

भोपाल (नगर संवाददाता)

राज्य शिक्षा केन्द्र कक्षा 5 वीं और 8 वीं की पुर्नपरीक्षा का परिणाम मंगलवार को दोपहर 2 बजे घोषित करेगी। राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल पर विद्यार्थी परिणाम देख सकते हैं।

विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था

प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र 16 से 23 जून के बीच उक्त पुर्नपरीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में प्रदेश के शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5 वीं के 1 लाख 17 हजार और कक्षा 8 वीं के 1 लाख 32 हजार समेत कुल 2.49 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में कुल 322 केंद्र बनाये गए थे। 17 हजार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई है।

निःशुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू

राजधानी समेत निजी स्कूलों में आरटीई की 30 प्रतिशत सीटें रह गईं रिक्त

भोपाल (नगर संवाददाता)

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीआई अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के निजी स्कूलों में लगभग 8 हजार स्कूलों की 21 हजार (30 फीसदी) सीटें रिक्त रह गई हैं। इन शालाओं में रिक्त सीटों को भरने तीसरे चरण में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया राज्य शिक्षा केंद्र ने शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आरएसके के अधिकारी अमिताभ अनुरागी के अनुसार प्रदेश

नहीं होगा कोई नया पंजीयन

आवेदन किया था। ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व चरणों में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे तृतीय चरण के लिए विद्यार्थी की कॉडिस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, वे आवेदक, जिन्हें पूर्व चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के विद्यालय चुन सकते हैं।

50 हजार सीटें रिक्त रह गई हैं। जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, पोर्टल पर स्कूलों का नाम सोमवार को प्रदर्शित कर दिया गया है।

स्वामी, मुद्रण, प्रकाशक एवं संपादक **आशीष दुबे** द्वारा साईं प्रिंटर्स, म. नं. 91, शाप नं. 3, जिन्सी पुलिस चौकी के पास जहांगीराबाद, भोपाल से मुद्रित एवं टी-2, बालाजी टावर, मधुवन बिहार कालोनी मिसरोद भोपाल से प्रकाशित। समस्त विवादों का न्यायालय भोपाल रहेगा।